गतांक की चीर-फ़ाड़

गौ-रक्षा के नाम पर सरकारी संरक्षण में गुण्डागर्दी

मज़दूर मोर्चा के 16-31 अक्तूबर 2017 के अंक में अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, व स्थानीय समसामयिक व ज्वलंत मुद्दों पर अनेक महत्वपूर्ण लेख प्रकाशित हुए हैं। केन्द्र में नरेन्द्र मोदी की भाजपा सरकार तथा विभिन्न राज्य की भाजपा सरकारों की मौन स्वीकृति और आरएसएस से जुड़े संगठनों से प्रोत्साहित गौ गुण्डों द्वारा गौ रक्षा व गौ हत्या के नाम पर की जा रही गुंडागर्दी व हिंसा का लेख 'गौमांस के बहाने भीड़ ने रस्सी में बांधकर पीटा' व 'मोदी-खट्टर: गौ गुन्डों के आगे लाचार, हर बार' में उचित विवेचन किया गया है। गौ-तस्करी के नाम पर तथाकथित गौ-तस्करों के विरुद्ध तो पुलिस कड़ी कार्यवाई करने में देर नहीं लगाती जब कि गौ गुन्डों द्वारा की जा रही हिंसा तथा यदि वह मांस गाय की वजाए किसी अन्य पशु का निकल जाए तो भी उन गुन्डों के विरुद्ध ऐसी हल्की धाराएं लगाई जाती हैं जिस कारण उनको तुरन्त जमानत मिल जाती है और वे बेखौफ़ होकर गौ-तस्करी के नाम पर अन्य शिकार ढूंढने निकल पड़ते हैं। प्रधान मंत्री मोदी कभी-कभी दिखावे के लिये गौ गुन्डों द्वारा की जा रही हिंसा की कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं जिसका इन गुंडों पर कोई असर नहीं पड़ता है। वास्तव में इन कार्यवाइयों से दलित व मुस्लिम वर्ग उत्पीड़ित हो रहा है और समाज में साम्प्रदायिक तनाव पनप रहा है।

प्रधान मंत्री मोदी झूठे आंकड़ों द्वारा अपनी योजनाओं की सफलता का प्रचार करने में माहिर है। नोटबंदी, जीएसटी, काला धन, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, नकली नोट के विरुद्ध कार्यवाई करने, अपनी सफलता की डींगे हांकने, अपनी पीठ थपथपाने तथा प्रचार करने में कोई भी मोदी का मुकाबला नहीं कर सकता। दिल्ली के विज्ञान भवन में कंपनी सचिवों के सम्मेलन में मोदी ने एक लाख लोगों को रोज़गार देने के जो आंकड़ें पेश किए उसका फ़र्जीवाड़ा लेख 'एक प्रधानमंत्री जो सच नहीं बोल सकता-अब रोजगार आंकड़ों का फ़र्जीवाड़ा' में पूरा पर्दाफ़ाश किया गया है।

प्रधान मंत्री मोदी पिछले कुछ समय से बार-बार कह रहे हैं कि लोक सभा व राज्य विधान सभाओं के चुनाव इकट्ठे होने चाहिये तथा अलग-अलग मंचों के सहारे देश में इस बहस को बढावा दिया जा रहा है। लेकिन जब गुजरात व हिमाचल प्रदेश विधान सभा के चुनावों के नोटिफिकेशसन का समय आया तो 12 अक्तूबर को चुनाव आयोग ने दोनों विधान सभा चुनावों के मतों की गणना के परिणाम की तारीख तो 18 दिसम्बर घोषित

कर दी परन्तु दो एक साथ चुनी गई विधान सभाओं के चुनाव एक साथ घोषित न करके चुनाव कार्यक्रम केवल हिमाचल प्रदेश का ही घोषित किया जिसके अनुसार वहां चुनाव 9 नवंबर को होंगे तथा आचार संहिता लागू हो गई। लेकिन आयोग के अनुसार गुजरात में अभी आचार संहिता लागू नहीं हुई और वहां के लिये नोटिफिकेशन भी बाद में ज़ारी किया जाएगा जिसका लेख 'चुनाव आयोग ने मोदी के आगे घुटने टेके' में वर्णन किया गया है। इस प्रकरण से कई प्रश्न खड़े होते हैं। यदि चुनाव गुजरात व हिमाचल प्रदेश की दो विधान सभाओं की चुनाव इकट्ठे नहीं करवा सकता तो लोक सभा व सभी विधान सभाओं के चुनाव इकट्ठे कैसे करवाए जाएंगे? जब वोटों की गिनती की तारीख 18 दिसम्बर घोषित कर दी तो गुजरात भी चुनावी मोड़ में आ गया इसलिये वहां भी आचार संहिता लागू होनी चाहिए थी। चुनाव आयोग ने अब गुजरात विधान सभा के चुनाव का 25 अक्तूबर को नोटिफिकेशन ज़ारी कर दिया कि वहां चुनाव 9 व 14 दिसम्बर को होंगे। गौरतलब है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने गुजरात में पहले ही घोषणा कर दी थी कि वहां चुनाव दिसम्बर के पहले सप्ताह में होंगे। स्पष्ट है कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र व निष्पक्ष आयोग की तरह कार्य न करके एक सरकारी विभाग की तरह कार्य कर रहा है जो प्रधान मंत्री के निर्देशन पर काम करता है।

आरएसएस द्वारा महात्मा गांधी व जवाहर लाल नेहरू की छवि को खराब करने की लगातार सुनियोजित साजिश, केन्द्र में मोदी सरकार बनने के बाद इन साजिशों को संस्थागत रूप देने, हिंदू आतंकवाद फ़ैलाने के आरएसएस से सम्बन्धित आरोपित संगठनों जैसे अभिनव भारत, सनातन संस्था आदि व इनसे जुड़े लोगों को अदालत से बरी करवाकर उनके चेहरे सम्मानजनक तरीके से जनता के सामने लाने के लिये चलाए जा रहे अभियान का लेख 'महात्मा गांधी से क्यों डरता है आरएसएस' में विवेचना की गई है। प्रधान मंत्री मोदी ने गुजरात में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में शिकायत भरे अंदाज में कहा कि कांग्रेस हम लोगों पर गांधी की हत्या का आरोप लगाती है। अभिनव भारत से जुड़े डॉ.फणनवीस द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका तथा प्रधान मंत्री मोदी व केन्द्रीय मंत्री उमा भारती के बयानों से सुप्रीम कोर्ट को स्पष्ट इशारा आरएसएस पर लगे काले धब्बे से छुटकारा देने व कांग्रेस को इसके लिये आरोपित करने का है।

गोधरा अग्नि संहार काण्ड में अहमदाबाद हाई कोई ने भाजपा की तत्कालीन मोदी की सरकार व केन्द्रीय रेल मंत्रायल की आपराधिक चूक तो बताया परंतु मुख्यमंत्री मोदी गृह मंत्री अमित शाह व केन्द्रीय रेल मंत्री नीतीश कुमार की कोई कानूनी जवाबदेही तय नहीं की शायद इसमें हिंदुत्व की राजनीति के कारण न्यायपालिका बेबस हो गई जिसका लेख 'पंडित पलायन हो या जलता गोधरा, हिंदुत्व को क्लीन चिट देना ही राज धर्म में सटीक विश्लेषण किया गया है।

आजकल देश में संघ परिवार से सम्बन्धित संगठनों से योगगुरू व्यवसायी रामदेव द्वारा चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करने का सोशल साइट्स व मीडिया में जोरदार अभियान चलाया जा रहा है। बहिष्कार केवल चीनी पटाखे व चीनी झालर का किया जा रहा है जबकि अन्य चीनी उत्पाद का नहीं। इसके विपरीत मोदी सरकार चीनी निवेश को भारत में आमंत्रित करने को आतुर रहती है। इस विरोधाभास का लेख 'बैठूं तेरी गोद में ... उखाड़ूं तेरी दाढी ...चीनी माल और देशभक्त बहिष्कार' तथा कार्टून 'मोदी पूरी दुनियां में घूम कर बोल रहे हैं कि भारत में निवेश करो और रामदेव बोल रहे हैं कि विदेशी कम्पनियां लूट रही हैं-इनमें सही कौन है? में तथ्यात्मक विश्लेषण किया गया है। गौरतलब है कि विदेशी कम्पनियों का भारत में 85 अरब डॉलर निवेश करने का प्रस्ताव है जिसमें अकेले चीनी कम्पनियों के निवेश का प्रस्ताव 42 प्रतिशत है।

आदिवासी व दलित युवा शिक्षा, गूगल व सोशल मीडिया से शिक्षित व प्रेरित होकर अपने शोषण व अत्याचार के विरुद्ध ब्राह्मणवादी प्रभुत्व व मिथकों को चुनौती दे रहे हैं जिसका लेख 'दलित युवाओं द्वारा ब्राह्मणवादी मिथकों को चुनौती दी जा रही है' में उजागर किया गया है।

भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के निमंत्रण पर आए क्यूबा क्रांति के दूत व महान गुरिल्ला क्रांतिकारी चे ग्वेरा से के पी भानुमति ने दिल्ली के अशोक होटल में ऑल इंडिया रेडियो के लिये उनका इंटरव्यू लिया था जिसका रेडियो पर प्रसारण मुश्किल से दो मिनट चला तथा 'न्यूज़रील' कार्यक्रम में इन्टरव्यू शामिल ही नहीं था। उस समय के लगभग सभी समाचार पत्रों ने ग्वेरा की यात्रा पूरी तरह गोल कर दी। लेख 'चे ग्वेरा और गांधी का भारत-चे ग्वेरा की भारत यात्रा के दौरान ऑल इंडिया रेडियो को दिया इंटरव्यू 31 जुलाई 1959' प्रकाशित करके पाठकों को चे ग्वेरा के विचारों से अवगत कराने का सराहनीय कार्य किया गया है, जिसके लिये मज़दूर मोर्चा बधाई का पात्र है।

-डॉ. जुगल किशोर गुप्ता

बेमिसाल भाजपाई तानाशाही.....

पेज तीन के शेष

अपनी दुकान पर ग्राहकों का इंतजार कर रहा था। दरअसल, उसकी दुकान पर किसी ग्राहक ने उसे चाइनीज लड़ियां बेचने के लिए टोका तो नोटबंदी और जीएसटी से परेशान दुकानदार नरेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री स्मृति इरानी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को गालियां देनी शुरू कर दीं। उस शख्स ने उसका विडीयो बना लिया। वह विडियो फेसबुक और वाट्सऐप पर गया तो वायरल हो गया। पलवल बीजेपी के नेताओं ने पुलिस पर दबाव बनाया कि इस दुकानदार को गिरफ्तार करो। पलवल की एसपी सुलोचना गजराज ने दुकानदार की फौरन गिरफ्तारी का आदेश दिया। थाने में उस दुकानदार ने कान पकड़कर तौबा कि आगे से वह मोदी तो क्या उनकी सात पुश्तों को भी गाली नहीं देगा।

लेकिन पुलिस ने जिस तत्परता से इस मामले में कार्रवाई की, उस पर तो सवाल उठे ही लेकिन तमाम गांवों में यही संदेश गया कि आम आदमी अब अपने प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को भी गाली या बुरा-भला नहीं कह सकता। अगर कहेगा तो जेल जाना पड़ेगा। इससे पहले आजाद भारत में यह नौबत नहीं आई थी कि कोई प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं कर सकता। ...लेकिन कम से कम बागपुर गांव के लोग तो सहम ही गए हैं कि वे प्रधानमंत्री का नाम गलती से भी नहीं ले सकते। ...अबकी बार मोदी सरकार का नारा उन्हें डराने लगा है।

सेल्फी कल्चर के पत्रकार

पत्रकार विनोद वर्मा से जब छत्तीसगढ़ पुलिस रायपुर हेडक्वॉर्टर में पूछताछ कर रही थी तो उधर दिल्ली में पत्रकारों का बहुत बड़ा खेमा निर्लज्जता से मोदी और अमित शाह से बगलगीर होकर सेल्फी ले रहा था। वो पत्रकार धन्य हुए जा रहे थे, जिन्हें भाजपा ने मोदी और अमित शाह से मिलने का मौका दिया था। किसी भी पत्रकार की जुर्रत नहीं थी कि वह मोदी या अमित शाह से सवाल करता कि बिना जांच से पहले विनोद वर्मा को क्यों गिरफ्तार किया गया...

...और मोदी वहां जानते हैं, पत्रकारों के सामने क्या कह रहे थे...वह फरमा रहे थे कि हर पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र का होना बहुत जरूरी है।...सोचिए जरा...जिस पार्टी ने अपने ही संगठन और उसकी सरकार ने देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं का कुचलने का कुचक्र रचा हो, उसे बाकी राजनीतिक दलों में लोकतंत्र की चिंता सता रही है।...ऐसे बहरुपिये आप लोगों ने पहले कभी देखे थे।...भारत जैसे बड़े देश का प्रधानमंत्री जो सालभर में पत्रकारों के साथ एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, कोई उनसे सीधा सवाल नहीं कर सकता, वह शख्स वहां गए दरबारी पत्रकारों को आंतरिक लोकतंत्र के बारे में बता रहा था।

भाजपा के खतरनाक मंसूबे

गुजरात की प्रयोगशाला में गोधरा कांड की साजिश, गुलबर्ग सोसायटी और नरोदा पाटिया जैसे नरसंहार को अंजाम देने के बाद अब संघ परिवार मीडिया को साधने के लिए कभी छत्तीसगढ़ में तो कभी महाराष्ट्र में तो कभी राजस्थान में नए-नए प्रयोग कर रहा है। मोदी के केंद्र की सत्ता में पहुंचने के बाद भारत का मीडिया वैसे ही डर गया है। खासकर ऐसे अखबार और टीवी चैनल जो पूंजीपतियों के पैसे से चलते हैं, उन्होंने मोदी के सामने पहले ही आत्मसमर्पण कर दिया है। लेकिन मीडिया में अभी भी एक ऐसा तबका है जो मोदी के विरोध में डटकर जुटा है। हाल ही में जब द वायर ने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के बेटे जय शाह की दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की का भंडाफोड़ किया तो वायर वेबसाइट को मुकदमों में फंसा दिया गया।

राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने पिछले हफ्ते विधानसभा में एक बिल पेश किया, जिसका नाम है - दंड विधियां राजस्थान संशोधन विधेयक, 2017 । यह विधेयक राज्य के सेवानिवृत्त एवं सेवारत न्यायाधीशों, मजिस्ट्रेटों और लोकसेवकों के खिलाफ ड्यूटी के दौरान किसी कार्रवाई को लेकर सरकार की पूर्व अनुमति के बिना जांच से उन्हें संरक्षण देने की बात की गई है। यह विधेयक बिना अनुमति के ऐसे मामलों की मीडिया रिपोर्टिंग पर भी रोक लगाता है।

राजस्थान में अगर यह कानून लागू हो गया तो धीरे-धीरे भाजपा शासित राज्य भी अपने यहां इसे लागू करेंगे। एडीटर्स गिल्ड, खुद राजस्थान भाजपा के सीनियर विधायक घनश्याम तिवारी, कांग्रेस आदि ने इसका डटकर विरोध किया है। विधेयक अभी पास नहीं हुआ है लेकिन एक अध्यादेश के जरिए इसे लागू करने की कोशिश जारी है। इससे मिलते-जुलते विधेयक महाराष्ट्र और गुजरात में भी लाए गए थे। लेकिन वो पारित नहीं हो सके।

फिल्म से भाजपा नाराज

तमिल सिनेमा अपने तमाम प्रयोगों के लिए जाना जाता है। ऐसे में जब बॉलिवुड का मेनस्ट्रीम सिनेमा लोगों के गुस्से और विचारों को धार देने वाली फिल्में नहीं बना पा रहा है तो दक्षिण भारत में ऐसे प्रयोग जारी हैं। हाल ही में तमिल में एक फिल्म मर्सल आई है। इसमें नोटबंदी से बर्बाद हुए आम लोगों और जीएसटी की वजह से कारोबारी लोगों को हो रही परेशानी को टिप्पणी के रूप में पेश किया गया है। फिल्म को भारतीय सेंसर बोर्ड ने बिना किसी परहेज के पास कर दिया लेकिन फिल्म जैसे ही रिलीज हुई, भाजपा ने इसका विरोध किया। उसने फिल्म निर्माता से मांग की कि नोटबंदी व जीएसटी वाले डायलाग हटाए जाएं। दक्षिण के सुपर स्टार और मर्सल के मुख्य हीरो विजय ने सरकार की इस तानाशाही का जब विरोध किया तो उनके यहां छापा मारा गया। विजय के टैक्स की जांच के लिए वहां खुफिया अधिकारी पहुंचे। यह सरकारी तानाशाही नहीं तो और क्या है। यही वह सरकार है जब उसके फर्जी स्वच्छता अभियान पर आधारित टॉयलेट एक प्रेम कथा जैसी फिल्में बनती हैं और उसके अभिनेता को राष्ट्रीय पुरस्कार तक दे दिया जाता है लेकिन जैसे ही सरकार के एक नोटबंदी व जीएसटी पर सवाल उठाने वाली मर्सल जैसी फिल्म बनती है तो सरकार आलोचना हजम नहीं कर पाती। बहरहाल, दिग्गज अभिनेता रजनीकांत, शत्रुघ्न सिन्हा व अन्य फिल्मी हस्तियों ने मर्सल का पुरजोर समर्थन किया। लेकिन भाजपा फिल्म से टिप्पणी हटवा कर ही मानी।

सोई हुई जनता, चौपट राजा

भारत नामक अंधेर नगरी में जनता सो रही है। उसके एक-एक स्तंभ पर हमले हो रहे हैं लेकिन जनता ऐसे नादिरशाहों के खिलाफ उठकर खड़ी होने को तैयार नहीं। वह नीरो के राज में बांसुरी बजा रही है। प्रेस की आजादी की रक्षा या उसके मौलिक अधिकारों की रक्षा करना जितना दायित्व पत्रकारों, लेखकों, कलाकारों का है, उससे भी ज्यादा जनता का कुछ फर्ज है। हम लोग मजदूर मोर्चा किन आवाजों को बुलंद करने के लिए निकाल रहे हैं...मर्सल फिल्म में नोटबंदी और जीएसटी का विरोध किनके के लिए किया जा रहा है...अब जब जनता ही सरकारी तानाशाही के विरोध में नहीं सामने आएगी तो जिनकी ड्यूटी सच कहने की है, वो कब तक और कहां तक इसे अंजाम देते रहेंगे।...जनता को अगर राजनीतिक नेतृत्व की प्रतीक्षा है तो उसे मायूसी हाथ लगेगी।...आप खड़े हो, नेतृत्व जनता में से ही निकलेगा।